

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, तर्ष 22, अंक - 342- बुधवार 14- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सशक्त समाचार

यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क लगाने का फैसला दिवाली तक टला



नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले देशभर के करोड़ों यूपीआई यूजर्स और दुकानदारों को राहत देने के मकसद से यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लेनदेन पर 15 अक्टूबर से लिए जाने वाले एमडीआर शुल्क को लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। यूपीआई और सर्विसेज स्टायरिंग कमेटी ने मंगलवार को 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में बताया कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेन्ट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 15 अक्टूबर से लागू होने वाले फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है और इसे दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, जिसकी तारीख अलग से बताई जाएगी। स्टायरिंग कमेटी ने जारी बयान में बताया कि उद्योग जगत, वाणिज्यिक संगठनों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटरों के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और वित्त मंत्रालय के सामने उठाई गई चिंताओं के बाद इस समयसीमा को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दशहरा, दिवाली और छठ की बंपर खरीदारी के बीच कारोबारियों और आम जनता को राहत देते हुए इस नियम को दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री मुरुगन का इस्तीफा राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ी पीएम को 5 पेज की चिट्ठी लिखी, कहा... तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करेंगे



नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी को 5 पेज की चिट्ठी में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ने की बात कही है। मुरुगन ने चिट्ठी में लिखा...मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। मैं तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपना समय देना चाहता हूँ। मुरुगन ने लिखा...आपके नेतृत्व में देश और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। वे गरीब परिवार से आते हैं और उनके माता-पिता मजदूरी करते थे। भाजपा और एबीवीपी में करीब 30 साल काम करते हुए उनका मूल मंत्र रहा है कि राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और खुद सबसे आखिर में। मंत्री और सांसद के रूप में जिम्मेदारी देने के लिए आपका आभार। तमिलनाडु के रहने वाले मुरुगन मद्रास प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। इसी साल 4 मई को आए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणामों में केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन तमिलनाडु की अविनाशी सीट से किस्मत आगमना रहे थे। वे दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 56,200 से ज्यादा वोट मिले।

बीम्सटेक देशों में आतंकवादियों को पनाह, भर्ती और प्रशिक्षण की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए : अमित शाह

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि बीम्सटेक क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क को पनाह देने, भर्ती करने, प्रशिक्षण देने और संसाधन जुटाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।

नई दिल्ली में पहली बीम्सटेक गृहमंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीम्सटेक क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा का एक अनिवार्य मंच बन गया है। गृह मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे आपसी सहयोग को व्यावहारिक व्यवस्था में बदलें, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और संबंधित एजेंसियों की क्षमता मजबूत हो। शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलता है। प्रत्येक सदस्य देश की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे सदस्य देशों की सुरक्षा में सहायक बननी चाहिए।



राष्ट्रीय कानूनों और लागू संधियों के अनुरूप पारस्परिक कानूनी सहायता तथा प्रत्यर्पण के जरिए अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे भगोड़े अपराधियों और आतंकवादियों को कानून के कटघरे में लाने में सहयोग करने की अपील की। गृहमंत्री ने कहा कि आपराधिक नेटवर्क सीमाओं के पार सक्रिय हैं और स्थानीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। एनिक्रिप्टेड संचार, सोशल

मीडिया, क्रिप्टोकॉर्रेसी, ड्रोन और डार्क वेब का इस्तेमाल आतंकवादी प्रचार, भर्ती, धन जुटाने और अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा है। इन चुनौतियों से प्रभावित देशों से निपटने के लिए खुफिया एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय निगरानी तंत्र और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सहयोग और समन्वय जरूरी है। मादक पदार्थों की तस्करी को गंभीर खतरा बताते हुए शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार केवल एक आपराधिक

गतिविधि नहीं, बल्कि युवाओं के जीवन, समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। उन्होंने कहा, 'मादक पदार्थों की तस्करी में कुछ भी गोलडन रूल नहीं है।' उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को आम तौर पर 'गोल्डन ट्रायंगल' कहा जाता है, उसे वह 'डेथ ट्रायंगल' कहना पसंद करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पूरे क्षेत्र को मिलकर प्रयास करना होगा।

शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से होने वाली कमाई संगठित अपराध को आर्थिक ताकत देती है और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में भी होता है। पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध इस्तेमाल और डार्क वेब के जरिए होने वाले लेनदेन से यह चुनौती और जटिल हो जाती है। उन्होंने मादक पदार्थों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी, वास्तविक समय में सूचना साझा करने, संयुक्त कार्यबल गठित करने, रसायनों के अवैध इस्तेमाल को रोकने तथा वित्तीय जांच और अवैध संपत्तियों को जब्त करने में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने मानव तस्करी को भी साझा सुरक्षा और मानवाधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती बताया।

भारत ने दुनिया को सस्ती दवाएं-टैलेंट दिया : पीएम मोदी बदले में क्रेडिट-रॉयल्टी भी नहीं ली, देश पहली बार ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का मेजबान



मोदी ने कहा... हमने 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन की सलाई की

पीएम ने कहा... हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैसा सीधे अकाउंट में पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। गवर्नमेंट और सिटिजन के बीच सीधा रास्ता बना है। कोविड के दौरान वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग का बड़ा महत्व था। तब कहा गया कि जिनके पास इसे बनाने की सामर्थ्य नहीं है, उन तक भी पहुंचेगी।

बनाना होना चाहिए, और भारत इसी राह पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा...भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। 2014 से

नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। पावर के पंज पर जो फोकस है, यही गवर्नर्स में भी जरूरी है। सरकार के पावर अथॉरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नागरिक, सरकार पर ही निर्भर हो जाए। इसी पर चलते हुए भारत ने एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।

मोदी बोले...ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम दुनिया का एक प्रमुख वैश्विक मंच

पीएम ने कहा, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम दुनिया का एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जहां अलग-अलग देशों के नेता, बड़े उद्योगपति, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था, कारोबार, निवेश, तकनीक और दुनिया में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। खास बात यह है कि भारत पहली बार इस फोरम की मेजबानी कर रहा है। इस साल की थीम 'एक बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना' है।

पावर दूसरों को एम्पावर करने के लिए होती है...

पीएम ने कहा- इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने। उनके अपने-अपने हित रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट जैसे इनीशिएटिव लिए। भारत किन विचारों को लेकर सामने आया, ये सबके सामने है। भारत जोड़ने और जुड़ने पर बल देता है। पावर दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। भारत रिलायबिलिटी और स्टैबिलिटी की बात करता है।

भारत ने जीते के लिए रॉयल्टी नहीं मांगी...

पीएम मोदी ने कहा...जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तब वह भारत से आती है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तब भारत के युवाओं पर भरोसा होता है। ये स्पष्ट है कि दुनिया को एक स्टडी पिलर की जरूरत होती है, तब भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है।

एआई हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रहा...

पीएम ने कहा...दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तभी दूसरा सामने आ जाता है। सफाई घेन हो, एनर्जी हो, मिनरल, पेमेंट्स या टेक्नोलॉजी, दबाव-दबबे का माध्यम बन रहे हैं। इन सबके बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रहा है। दुनिया के सामने बड़ा सवाल भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सफाई जारी रहेगी। भरोसा ये कि जो वादे किए वो निभाए जाएंगे। संकट के समय पार्टनर कंट्री साथ रहेगी। भारत इसी सोच के साथ सामने है।

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे, जितना समय लगे, आंदोलन जारी रहेगा : राहुल गांधी



राहुल बोले...हमारा संघर्ष नहीं टूटेगा, जीत हासिल होगी...

राहुल गांधी ने कहा... विपक्ष का संघर्ष जारी रहेगा और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कल, परसों या दो साल भी लग जाएं, उनकी टीम रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा...जिस ऊर्जा, ताकत और एकजुटता के साथ हमने आंदोलन किया है, उसी भावना के साथ मिलकर लड़ते रहेंगे।

राहुल गांधी बोले...देश में लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था बर्बाद हो गई...

राहुल गांधी ने कहा...इस देश में लोकतंत्र बर्बाद कर दिया गया है। चुनाव व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया है। संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है, उसी भावना के साथ लोकतांत्रिक शासन, सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए एक साथ लड़ रहे हैं।

का अधिकांश भी छिन लिया जाएगा और वे चुप रहेंगे, तो बीजेपी गलतफहमी में है।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। एफआईआर के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लाक के नेताओं ने राहुल गांधी के घर चाय पर बैठक की। करीब दो घंटे चली इस बैठक के बाद सभी नेता एक साथ बाहर आए और मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा...मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना हमारा मिशन है। इसमें जितना भी समय लगे, एक दिन, एक साल या दो साल, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राहुल ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए अंत तक संघर्ष करेगा। आठ दिन में यह विपक्षी नेताओं की छठी बैठक थी। इसमें सुषिमा सुले, डी. राजा, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत कई नेता शामिल हुए। CPI(M) नेता एमए बेबी ने कहा...भाजपा वोट, विरोध प्रदर्शन की जगह और लोकतंत्र को छीन रही है। सरकार ने तय कर लिया है कि जंतर-मंतर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए नहीं किया जा सकता। हम सरकार की इस सोच को चुनौती देंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और अन्य लोगों को समझना होगा कि संविधान को नुकसान पहुंचाकर बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे लोगों को

न्याय के कटघरे में लाया जाएगा देश में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। चुनावी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया गया है और संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है। यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, भारत के लोगों और उनके भविष्य के लिए है। हम सभी मिलकर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए अंत तक लड़ेंगे। कोई भी संस्था अपनी भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक विरोध जारी रहेगा, जनता का संघर्ष जारी रहेगा और अंत में उसकी जीत होगी।

नेहा चोपड़ा बोलीं...बीजेपी लोकतंत्र और संविधान की दुरमन

नेहा बोरा ने कहा...अगर बीजेपी सोचती है कि वह लोकतंत्र की नींव पर हमला कर सकती है। और जब लोग अपने वोटिंग अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर उतरें, तो उनका विरोध करने



फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत ने इन नेताओं को 50 हजार रुपये के बांड पर एक साल तक शांति और

सदाचार बनाए रखने की शर्त पर जमानत दी थी, जिसके बावजूद यह कदम उठाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आशुतोष रांका, सौरव दास और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। दूसरी तरफ, कांग्रेस की छत्र इकाई एनएसयूआई ने राजीव चौक और कर्नाट प्लेस के पास अचानक 'फ्लैश प्रोटेस्ट' शुरू कर दिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित 'वोट चोरी' और जंतर-मंतर को दोबारा धरना स्थल के रूप में बहाल

करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एनएसयूआई ने दिल्ली पुलिस पर शांतिपूर्ण छत्रों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट तथा बर्बरता का गंभीर आरोप लगाया। संगठन ने कहा कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी और उनका संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर को एक अभिसूचना जारी कर जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया था।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेजस में उड़ान भरकर खत्म किया अपना फ्लाइटिंग करियर जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर अपने कार्यकाल की आखिरी फाइटर जेट उड़ान भरी

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर एक्सरसाइज 'तरंग शक्ति' के दौरान स्वदेशी तेजस पर अपने कार्यकाल की आखिरी फाइटर जेट उड़ान भरी। वह इस महीने के आखिर में रिटायर होने वाले हैं। दोस्त विदेशी देशों के एयरक्राफ्ट और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के साथ थीम 'पावर इन पार्टनरशिप' के साथ उनकी यह उड़ान एक ऐसे फाइटर पायलट के जल्बे को दिखाती है, जो हमेशा आगे रहकर लीड करने में यकीन रखता है। वायु सेना के स्थापना दिवस पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि आपके पास अपने करियर के दौरान विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड और रोटरी विंग विमानों पर 5,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने पर तेजस मार्क-2 न उड़ाने का मतलब रहेगा, तो एयर चीफ ने कहा था कि जीवन के सभी लक्ष्य पूरे नहीं होते, जो पूरे होते हैं उनका स्वागत करना चाहिए और जो अधूरे हैं, उन्हें आने वाले के लिए छोड़ देना चाहिए। स्वदेशी तेजस में अपनी आखिरी फाइटर उड़ान उनके शानदार करियर का एक अहम पल है, जो उड़ान के पक्के जुनून और देश की सेवा के पक्के इरादे



श्रीलंका, यूएई और अमेरिका ने एयर एसेट्स भेजे हैं। बाकी 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए हैं। वायु सेना प्रमुख ने इन्हीं विदेशी जेट और सूर्यकिरण के साथ उड़ान भरते हुए अपने प्फाइंग करियर के एक यादगार चैप्टर को खत्म किया है। एयर चीफ ने अपनी आखिरी उड़ान के लिए भारत में बना फाइटर जेट चुना, जो तेजस पर उनका भरोसा दिखाता है। चीफ के तौर पर लगभग दो साल बाद वह 31 अक्टूबर को फाइटर पायलट को पद मौजूदा वाइस चीफ को सौंप देंगे।

बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर फिर सवाल

फरारी के बाद सुरक्षा और जिम्मेदारी की जांच जरूरी



निलंबन खत्म,फिर उसी दिन फरारी! तीन सदस्यीय जांच के बाद नीतू कुशवाहा को मिली वापसी,पदभार संभालने के कुछ घंटे बाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बालक फरार

अंतिम चेतावनी देकर बहाली,फिर छह बालक फरार...12 अक्टूबर के आदेश पर सवाल—जिस अधीक्षक का निलंबन खत्म किया,उसी दिन संस्थान की सुरक्षा फिर कठघरे में...

फिर फरारी,फिर सवाल! प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 अपचारी बालक भागे,दो पकड़े गए,चार की तलाश जारी

25 की क्षमता वाले संस्थान में 63 बच्चे; निलंबित प्रभारी अधीक्षक ने दो महीने बाद संभाला पदभार,उसी शाम फरारी... संयोग या व्यवस्था की बड़ी चूक?

अधिशर्क: रसोइये पर गर्म खाना फेंककर हंगामा,ड्यूटी गार्ड को कमरे में बंद कर भागे बालक,पुराने मामलों में भी कई बच्चों का पता नहीं,जिला बाल संरक्षण अधिकारी की कार्यप्रणाली और काउंसिलिंग व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल...



—न्यूज डेस्क—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले की बाल संरक्षण व्यवस्था में अपचारी बच्चों के फरार होने का शिलसिला धमने का नाम नहीं ले रहा है,प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह से लगातार सामने आ रही फरारी की घटनाओं के बीच अब एक बार फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी से छह अपचारी बालकों के फरार होने का मामला सामने आया है, पुलिस ने तलाश अभियान के दौरान दो बालकों को पकड़ लिया है,जबकि चार अन्य की तलाश जारी है,इस बार घटना के दौरान रसोइये पर गर्म खाना फेंककर हंगामा करने और ड्यूटी पर तैनात गार्ड को कमरे में बंद करने की बात सामने आई है,घटना ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ संस्थान के भीतर के माहौल,बच्चों के व्यवहार,काउंसिलिंग और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 25 बच्चों की क्षमता वाले प्लेस ऑफ सेफ्टी में कथित तौर पर 63 अपचारी बालक निवासरत थे, यानी निर्धारित क्षमता से 38 अधिक बच्चे, आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को रखने के दौरान सुरक्षा,निगरानी,भोजन,आवास, परामर्श के संख्या के अनुरूप सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग को देना चाहिए,इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। जानकारी के अनुसार, जिस दिन छह बालक फरार हुए,उसी दिन दोपहर करीब 12 बजे निलंबित प्रभारी अधीक्षक नीतू राम कुशवाहा ने लागभग दो महीने बाद फिर से पदभार संभाला था,शाम करीब सात बजे फरारी की घटना सामने आ गई,पदभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद हुई इस घटना ने परिस्थितियों को और चर्चा में ला दिया है,हालांकि केवल समय के इस संयोग से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी या घटना से उसका संबंध साबित नहीं होता,लेकिन यह जरूर सवाल उठता है कि पदभार ग्रहण करने के बाद संस्थान की वास्तविक स्थिति क्या थी और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी,छह बच्चों की नई फरारी और उसी दिन पदभार संभालने का घटनाक्रम इस बहाली आदेश के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है,यदि नीतू राम कुशवाहा ने 12 अक्टूबर को दोपहर लागभग 12 बजे पदभार संभाला और उसी शाम करीब 7 बजे छह बच्चे फरार हुए,तो यह जानना जरूरी है कि तीन सदस्यीय जांच समिति ने निलंबन समाप्त करने की अनुशंसा किन तथ्यों के आधार पर की? जांच प्रतिवेदन में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों और अधीक्षक की जिम्मेदारी के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले गए? अंतिम चेतावनी के बाद उन्हें दोबारा उसी संवेदनशील संस्थान का प्रभार देने का आधार क्या था? क्या पदभार ग्रहण करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी? नई फरारी के बाद क्या बहाली आदेश और जांच समिति के निष्कर्षों की दोबारा समीक्षा होगी? दोपहर 12 बजे पदभार,शाम 7 बजे फरारी...संयोग या व्यवस्था की विफलता?—इस घटना का सबसे चर्चित पहलू

25 की क्षमता,63 बच्चे... आखिर कैसे संभल रही थी व्यवस्था?

प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्देश्य केवल अपचारी बच्चों को एक स्थान पर रखना नहीं,बल्कि उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना,उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझना और सुधार की प्रक्रिया से जोड़ना भी है, ऐसे संस्थान में बच्चों की संख्या निर्धारित क्षमता से काफी अधिक होना अपने आप में गंभीर समीक्षा का विषय है,यदि 25 बच्चों की क्षमता वाले संस्थान में 63 बच्चे रह रहे थे,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त जगह,निगरानी, भोजन,स्वास्थ्य सुविधा और व्यक्तिगत परामर्श उपलब्ध था? क्या सुरक्षाकर्मियों की संख्या बच्चों की वास्तविक संख्या के अनुरूप थी? क्या ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया था? क्या परिसर के प्रवेश और निकास द्वारों की सुरक्षा पर्याप्त थी? इस बार सामने आए घटनाक्रम के अनुसार,बालकों ने पहले रसोई के पास गर्म खाना फेंककर हंगामा किया,इसके बाद ड्यूटी पर तैनात गार्ड को कमरे में बंद कर दिया और संस्थान से बाहर निकल गए,इस घटनाक्रम से सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद संभावित कमजोरियों की जांच जरूरी हो जाती है,यह भी जांच का विषय है कि घटना के समय कितने कर्मचारी ड्यूटी पर थे, बच्चों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी और हंगामे के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने क्या कदम उठाए।

निलंबित प्रभारी अधीक्षक नीतू राम कुशवाहा की वापसी से जुड़ा है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार,करीब दो महीने बाद उन्होंने घटना वाले दिन दोपहर लागभग 12 बजे पदभार ग्रहण किया,उसी शाम करीब सात बजे छह अपचारी बालकों के फरार होने की घटना सामने आ गई, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर निलंबित प्रभारी अधीक्षक को पदभार सौंपने की प्रक्रिया किस आधार पर पूरी की गई? क्या पदभार ग्रहण करने से पहले संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी? क्या उन्हें पूर्व में हुई फरारी की घटनाओं,सुरक्षा संबंधी निर्देशों और लंबित सुधारात्मक कार्यों की जानकारी दी गई थी? यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पदभार ग्रहण करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की गई थी या नहीं,हालांकि सात घंटे के भीतर हुई घटना को सीधे पदभार ग्रहण करने से जोड़कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन जब संस्थान में पहले से कई फरारी की घटनाएं हो चुकी हों, तब नए सिरे से जिम्मेदारी संभालने के समय सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाता है,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस संस्थान में पहले ही बार-बार सुरक्षा चूक हो चुकी थी,वहां व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए थे?

पुराने मामलों में फरार बच्चों की वापसी पर भी स्पष्टता जरूरी-पिछली घटनाओं के बाद कितने बच्चे वापस आए गए, कितनों को पुलिस ने पकड़ा और कितने अब भी लापता हैं?...इसकी एक स्पष्ट और अधिकारिक स्थिति सामने आनी चाहिए, आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,एक पूर्व घटना में पांच बच्चों के फरार होने के बाद केवल एक की वापसी हुई थी,जबकि चार का पता नहीं चलने की बात कही जा रही है,इस विवरण की संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से पुष्टि आवश्यक है,यदि पूर्व मामलों के कुछ बच्चे अब भी नहीं मिले हैं,तो यह और गंभीर विषय है, ऐसे में केवल नई फरारी की घटना पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा, प्रत्येक मामले में फरार बच्चों की वर्तमान स्थिति,तलाश की कार्रवाई और संस्थान में वापसी का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए,इससे यह भी पता चलेगा कि प्रशासन पुराने घटनाओं से कितना सबक ले पाया है और फरार बच्चों की तलाश में पुलिस तथा बाल संरक्षण विभाग के बीच कितना समन्वय रहा है।

काउंसिलिंग व्यवस्था पर भी सवाल...बच्चे भागना क्यों चाहते हैं?—इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों की

मानसिक स्थिति और काउंसिलिंग व्यवस्था का भी है,आखिर बच्चे बार-बार संस्थान से बाहर निकलने का जोखिम क्यों उठा रहे हैं? क्या यह केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का परिणाम है,या बच्चों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में भी कहीं कमी रह रही है? इसी तरह,केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर देना भी पर्याप्त नहीं होगा,यदि बच्चों की शिकायतों,तनाव,आपसी विवाद और व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने की व्यवस्था प्रभावी नहीं है,जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि घटना से पहले बच्चों के बीच कोई विवाद हुआ था या नहीं,किसी ने शिकायत की थी या नहीं और कर्मचारियों ने किसी असामान्य व्यवहार की सूचना अधिकारियों को दी थी या नहीं,यदि बच्चों के मन में असंतोष या भय है, तो उसकी पहचान और समाधान के लिए नियमित व्यक्तिगत परामर्श तथा शिकायत सुनने की निष्पक्ष व्यवस्था जरूरी है।

जिला कार्यालय में काउंसलर, फिर संस्थानों में परामर्श व्यवस्था कैसी?—आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार,जिला बाल संरक्षण कार्यालय में पहले से एक काउंसलर मौजूद है,जबकि बाल संरक्षण संस्थानों से जुड़े दो काउंसलरों के भी जिला कार्यालय में सेवाएं देने की बात सामने आई है, यदि यह स्थिति सही है,तो यह जांच का विषय है कि संवेदनशील संस्थानों में बच्चों की नियमित काउंसलिंग किस प्रकार की जा रही है, क्या संस्थान में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श मिलता है? क्या बच्चों की मानसिक स्थिति और व्यवहार में बदलाव का रिकॉर्ड रखा जाता है? क्या गंभीर तनाव या विवाद की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप किया जाता है? यदि संस्थानों के लिए नियुक्त काउंसलर वास्तव में जिला कार्यालय में काम कर रहे हैं,तो उनके पदस्थापन आदेश,कार्य-विवरण और उपस्थिति रिकॉर्ड की समीक्षा की जानी चाहिए,यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिला कार्यालय और संस्थानों में काउंसलिंग की जिम्मेदारी का बंटवारा किस आधार पर किया गया है, यदि संस्थानों में बच्चों की संख्या क्षमता से काफी अधिक है,तो परामर्श सेवाओं की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ती है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल-बार-बार फरारी की घटनाओं के बाद अब जिला बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे

फरारी का पुराना रिकॉर्ड भी कम गंभीर नहीं...

प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह से वर्ष 2026 में लगातार बच्चों के फरार होने की घटनाएं सामने आई हैं,इससे पहले भी इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं।

तारीख	संस्थान	फरार बच्चों की संख्या
17 फरवरी 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी	15
24 जून 2026	बाल संप्रेक्षण गृह	11
14 जुलाई 2026	बाल संप्रेक्षण गृह	13
23 जुलाई 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी	3
12 अक्टूबर 2026 की रात बनाई गई घटना	प्लेस ऑफ सेफ्टी	6

अंतिम घटना की तारीख 13 अक्टूबर को प्रकाशित विवरण के आधार पर पिछली रात की मानी गई है,घटना की आधिकारिक तारीख और पूर्व मामलों में बच्चों की बरामदगी की स्थिति की पुष्टि संबंधित अभिलेखों से की जानी चाहिए,इन घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह अब किसी एक दिन की आकस्मिक चूक का मामला नहीं रह जाता,लगातार होने वाली फरारी संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था,निगरानी और सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है, पहली घटना के बाद यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी,तो दूसरी घटना कैसे हुई? दूसरी घटना के बाद समीक्षा हुई थी,तो तीसरी बार 13 बच्चे कैसे फरार हो गए? जुलाई की घटना के बाद भी यदि सुधारात्मक कदम उठाए गए थे,तो अब फिर छह बच्चे किस तरह बाहर निकल गए? हर बार जांच और सुरक्षा मजबूत करने की बात सामने आती है,लेकिन फरारी की घटनाओं का दोहराया जाना यह मांग करता है कि इस बार केवल घटना की जांच नहीं,बल्कि पिछले मामलों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाए।

हैं,जिला स्तर पर संस्थानों के निरीक्षण, सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान, निर्देशों के पालन की समीक्षा और बच्चों की देखभाल से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित संस्थानों का निरीक्षण कब-कब हुआ,निरीक्षण में क्या कमियां मिलीं और उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए,यदि सुरक्षा संबंधी कमियां पहले से दर्ज थीं, तो क्या उन्हें दूर करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी? यदि निर्देश दिए गए थे,तो उनके पालन की पुष्टि किसने की? और यदि निरीक्षण में कोई बड़ी कमी नहीं मिली थी,तो बार-बार बच्चों के फरार होने की घटनाओं का कारण क्या रहा? जिला बाल संरक्षण अधिकारी की भूमिका की समीक्षा का अर्थ पहले से दोषी घटना और गार्ड को कमरे में बंद किए जाने के आरोपों की भी जांच आवश्यक है,यदि किसी कर्मचारी को चोट पहुंची है,तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण और बयान दर्ज किया जाना चाहिए,पुलिस की कार्रवाई के साथ विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाकी बच्चों की सुरक्षा प्रभावित न हो और घटना के बाद परिसर में सुरक्षा संबंधी कमियों को तत्काल दूर किया जाए।

अब प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना होगा

- 25 की क्षमता वाले संस्थान में 63 बच्चे क्यों रखे गए थे?
- क्या अतिरिक्त बच्चों की संख्या के अनुरूप कर्मचारियों और सुरक्षा संसाधनों की व्यवस्था थी?
- निलंबित प्रभारी अधीक्षक को दो महीने बाद पदभार सौंपने का निर्णय किन

आधारों पर लिया गया?

- पदभार ग्रहण करने के दिन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई थी या नहीं?
- पुराने मामलों में फरार हुए कितने बच्चे वापस आए गए और कितने अब भी लापता हैं?
- संस्थान में नियुक्त काउंसलरों की वास्तविक पदस्थापना और कार्यस्थल क्या है?
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पिछली घटनाओं के बाद कौन-कौन से निरीक्षण और सुधारात्मक कदम उठाए?
- क्या सभी फरारी की घटनाओं की संयुक्त समीक्षा कर जिम्मेदारी तय की जाएगी?

बच्चे भाग रहे हैं, व्यवस्था को अपनी कमियां तलाशनी होंगी-प्लेस ऑफ सेफ्टी से छह अपचारी बालकों की ताजा फरारी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि समस्या को केवल सुरक्षा कर्मियों की संख्या या दीवारों और दरवाजों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता,निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का निवास, बार-बार फरारी,पुराने मामलों में बच्चों की वापसी को लेकर अस्पष्टता और काउंसिलिंग व्यवस्था पर उठते सवाल—इन सभी पहलुओं की एक साथ समीक्षा जरूरी है,सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के फरार होने को न तो सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही बिना जांच के इसे प्रताड़ना का प्रमाण माना जा सकता है, प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा,उनके अधिकारों और संस्थान की जवाबदेही—तीनों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए,अब सवाल केवल यह नहीं है कि छह बच्चे कैसे भागे,बल्कि यह भी है कि पिछली घटनाओं के बाद व्यवस्था में क्या बदला, क्षमता से अधिक बच्चों को रखने की नीबट क्यों आई और निगरानी तंत्र ने अपनी जिम्मेदारी कितनी प्रभावी ढंग से निभाई,जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलते और सुधार जमीन पर दिखाई नहीं देता,तब तक बाल संरक्षण व्यवस्था पर उठते सवाल खत्म होने वाले नहीं हैं।

आदेश में सामने आए 5 बड़े तथ्य...

- निलंबन समाप्त: आदेश में उल्लेख है कि 24 जुलाई 2026 के आदेश से नीतू राम कुशवाहा को निलंबित किया गया था।
- तीन सदस्यीय जांच समिति: कलेक्टर/अध्यक्ष,जिला बाल संरक्षण समिति के आदेशानुसार गठित समिति ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- अंतिम चेतावनी: जांच प्रतिवेदन के आधार पर नीतू राम कुशवाहा को भविष्य के लिए अंतिम चेतावनी जारी करते हुए निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया।
- फिर मिली जिम्मेदारी: उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) एवं शासकीय विशेष गृह (बालक),अम्बिकापुर के प्रभारी अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया।
- बहाली अवधि का वेंतन: आदेश में 24 जुलाई 2026 से बहाली तक की निलंबन अवधि को कर्तव्यावधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

केशवपुर डीएमएफ मामले में बड़ा न्यायिक आदेश,1.32 करोड़ की कथित गड़बड़ी पर 9 के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

आत्मानंद महाविद्यालय के विकास कार्यों में बिना निविदा भुगतान और बिल-वाउचर को लेकर उठे सवाल,पूर्व जनपद सीईओ,इंजीनियर,सरपंच-सचिव और निर्माण फर्मों जांच के दायरे में

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

सरकारी धन से विकास कार्य कराने के नाम पर यदि नियमों की अनदेखी और भुगतान में अनियमितता के आरोप सामने आते हैं,तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। सरगुजा जिले के केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के विकास कार्यों से जुड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) का मामला अब इसी सवाल को लेकर चर्चा में है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की राशि से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नौ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पर यह आदेश दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महाविद्यालय के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत राशि के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई। अब पुलिस विवेचना में यह स्पष्ट होगा कि भुगतान किस प्रक्रिया के तहत हुआ,निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या थी और संबंधित अधिकारियों,पंचायत पदाधिकारियों तथा निर्माण फर्मों की क्या भूमिका रही।

तीन कार्यों के लिए स्वीकृत हुए थे 1.32 करोड़ रुपये

प्राथ्ी के अनुसार, 31 मार्च 2023 को केशवपुर स्थित महाविद्यालय के विकास के लिए तीन अलग-अलग प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई थीं। गार्डन सौंदर्यीकरण और सीसी



रोड निर्माण के लिए 33 लाख 24 हजार रुपये, प्रथम तल पर प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के नवीनीकरण तथा अहता निर्माण के लिए 49 लाख 57 हजार रुपये और भूतल पर प्राचार्य कक्ष, कार्यालय नवीनीकरण तथा पार्किंग शेड निर्माण के लिए 49 लाख 52 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे। तीनों कार्यों की कुल स्वीकृत राशि 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये थी। इन कार्यों के लिए ग्राम पंचायत केशवपुर को निर्माण एजेंसी बनाया गया था। शिकायत में आरोप है कि तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ सुरेश्वर नाथ तिवारी और उपअभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरपंच-सचिव के माध्यम से दो निर्माण फर्मों को भुगतान कराया। आरोप के मुताबिक,खुली निविदा और निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना मेसर्स अन्नया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स तथा मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन,कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर्स को आरटीजीएस और चैक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। प्राथ्ी ने यह भी आरोप



फर्म के दस्तावेज में इंजीनियर का मोबाइल नंबर होने का दावा

मामले में एक महत्वपूर्ण आरोप यह भी है कि स्मृति कंस्ट्रक्शन से संबंधित शासकीय दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर तत्कालीन उपअभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर का था। प्राथ्ी के अनुसार,सरपंच और सचिव ने भी अधिकारियों के दबाव में हस्ताक्षर करने की बात कही थी। यदि इन तथ्यों की पुष्टि होती है,तो यह जांच का महत्वपूर्ण पहलू होगा। पुलिस को फर्म के पंजीयन दस्तावेज,बैंक खाते,भुगतान विवरण,बिल-वाउचर और संबंधित व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक संबंधों की जांच करनी होगी। केवल मोबाइल नंबर दर्ज होने या किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता।

लगाया है कि निर्माण कार्यों के संबंध में पंचायत को आवश्यक बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए। इन आरोपों की पुष्टि अब मूल भुगतान अभिलेखों,कार्यादेश,माप पुस्तिका और तकनीकी जांच के आधार पर होगी।

कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में भी अनियमितताओं का उल्लेख : प्राथ्ी के मुताबिक,तत्कालीन जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव की शिकायत के बाद कलेक्टर सरगुजा ने चार सदस्यीय जांच दल गठित किया था। इसमें डिप्टी कलेक्टर राम सिंह

उत्कुर,लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह,जिला पंचायत की एडीपीओ नेहा सिंह और सहायक कोषालय अधिकारी मनोज कुमार शर्मा शामिल थे। शिकायत में दावा किया गया है कि जांच दल ने स्वीकृत प्राक्कलन और तकनीकी नियमों के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत किया था। न्यायालय ने उपलब्ध विवरण के अनुसार जांच दल के सदस्यों के विरुद्ध अपराध बनता नहीं माना,क्योंकि वे जांच समिति में शामिल थे।

लोकसेवक होने से नहीं मिलता हर आरोप में संरक्षण...

सुनवाई के दौरान लोकसेवकों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण का मुद्दा भी उठा। उपलब्ध विवरण के अनुसार,न्यायालय ने आरोपित कृत्यों की शासकीय दायित्व का हिस्सा मानकर संरक्षण देने की दलील स्वीकार नहीं की। हालांकि,एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और आरोपों की सत्यता का निर्धारण पुलिस विवेचना तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

2024 में भी सामने आई थी उन्नयन कार्यों को लेकर खबर...

अगस्त 2024 में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में भी केशवपुर स्थित आत्मानंद महाविद्यालय के उन्नयन के नाम पर डीएमएफ राशि के उपयोग को लेकर आरोपों का उल्लेख किया गया था। उस रिपोर्ट में करीब 1.81 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया था। वर्तमान न्यायालयीन प्रकरण के उपलब्ध विवरण में तीन कार्यों की स्वीकृत राशि 1.32 करोड़ 33 हजार रुपये बताई गई है। दोनों आंकड़ों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए मूल स्वीकृति आदेशों और भुगतान अभिलेखों का मिलान आवश्यक है।

अब यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और संबंधित कार्यों की गुणवत्ता तथा भुगतान का स्वतंत्र तकनीकी सत्यापन कराया गया या नहीं।

विद्यार्थियों को मिली सुविधाएं या केवल कागजों में पूरे हुए काम? इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विकास कार्यों के नाम पर स्वीकृत राशि का वास्तविक लाभ महाविद्यालय और विद्यार्थियों को कितना मिला। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय,अहता और पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद उनकी वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है। यदि भुगतान के अनुपात में काम नहीं हुआ या निर्धारित गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया, तो यह सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। इसके लिए स्थल निरीक्षण, माप पुस्तिका,तकनीकी मूल्यांकन और भुगतान दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए।

अब पुलिस विवेचना पर टिकी निगाहें...

न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करनी होगी। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राशि किसके आदेश पर जारी हुई, भुगतान किन खातों में गया, निर्माण किसने कराया और कार्यों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग का नाम पर स्वीकृत राशि का वास्तविक लाभ महाविद्यालय और विद्यार्थियों को कितना मिला। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय,अहता और पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद उनकी वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है। यदि भुगतान के अनुपात में काम नहीं हुआ या निर्धारित गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया, तो यह सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। इसके लिए स्थल निरीक्षण, माप पुस्तिका,तकनीकी मूल्यांकन और भुगतान दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए।

नवाचार से रोजगार सृजन की ओर बढ़ें विद्यार्थी केवल नौकरी तक सीमित न रखें सोच राजीव गांधी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज पर जागरूकता कार्यक्रम,200 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल से समाज की समस्याओं का समाधान करना तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। विद्यार्थियों को इसी सोच के साथ नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश मंगलवार को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बिकापुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज जागरूकता कार्यक्रम में दिया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के सहायक प्रबंधक सचोदय कुमार साहू और प्रबंधक अश्विनी शुक्ला ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को नवाचार,उद्यमिता,स्वरोजगार और उद्योग विकास की संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक और बाजार व्यवस्था के दौर में नए विचारों के साथ समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तलाशना जरूरी है। नवाचार का अर्थ केवल नई मशीन या तकनीक विकसित करना नहीं है,बल्कि किसी मौजूदा सेवा,प्रक्रिया या व्यवसाय को अधिक सरल, किफायती और प्रभावी बनाना भी है। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से अपने आसपास की समस्याओं को पहचानकर उनके समाधान के लिए नए विचार विकसित करने का आह्वान किया। कृषि,शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यावरण, परिवहन और स्थानीय बाजार जैसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे विचार भी भविष्य में उपयोगी व्यवसाय और रोजगार के अवसर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी विचार को सफल बनाने के लिए उसकी उपयोगिता,लागत,बाजार की मांग और संभावित लाभार्थियों की जरूरतों को समझना जरूरी है। इसके साथ ही उचित योजना, टीम भावना,निरंतर प्रयास और व्यावहारिक क्रिया-व्ययन भी महत्वपूर्ण हैं।



स्थानीय संसाधनों में उद्यमिता की संभावनाएं : सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में वक्ताओं ने कृषि आधारित गतिविधियों,वन उत्पादों,हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं से जुड़े व्यवसायों की संभावनाओं पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के आधार पर ऐसे व्यावसायिक विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया,जिनसे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार हों। वक्ताओं ने कहा कि उद्यमिता के लिए बाजार की मांग,उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि,विपणन और वित्तीय बंधनों की समझ भी जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने विषयगत ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ते हुए ऐसे समाधान तलाशने चाहिए,जिनका सामाजिक और आर्थिक महत्व हो। वाणिज्य एवं प्रबंधन के विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग व्यावसायिक योजनाएं बनाने और उद्यमों के संचालन में कर सकते हैं। कार्यक्रम में रचनात्मक सोच,आत्मनिर्भरता, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की दक्षता विकसित करने पर भी जोर दिया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि नवाचार केवल वैज्ञानिकों या बड़े उद्योगपतियों तक सीमित नहीं है।

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

महिलाओं और बालिकाओं को हुनरमंद बनाने,उनकी प्रतिभा निखारने और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सेवा किटी समूह ने अभिरुचि केंद्र की शुरुआत की है। शुभारंभ अवसर पर महापौर श्रीमती मंजुषा भगत ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र महिलाओं को कुछ नया सीखने,अपनी प्रतिभा विकसित करने और अपने हुनर को अजीबिका से जोड़ने का अवसर देगा। वहीं, एमआईसी सदस्य श्रीमती श्वेता गुप्ता ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते दौर में महिलाओं और बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है,ताकि वे नए कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें। शिवाजी चौक, गुदरी बाजार के पास श्रीमती सुधा वर्मा के निवास पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर मंजुषा भगत,एमआईसी सदस्य श्वेता गुप्ता, सुधा वर्मा तथा सेवा किटी की वरिष्ठ सदस्य संतोष पांडे, जया तिवारी और कुंजबाला जायसवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सेवा किटी की संस्थापिका वर्द्धा दत्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्र की स्थापना के उद्देश्य और संघटन की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से शहर की 60 सेवा भावी महिलाओं के सहयोग से सेवा किटी लगातार जनहित के कार्य कर रही है। अभिरुचि केंद्र इसी प्रयास का विस्तार है,जहां महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर



उनकी रुचि और प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्न की बर्बादी रोकने की पहल भी उठाई : कार्यक्रम में भोजन की बर्बादी रोकने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। वर्द्धा दत्ता ने बताया कि सेवा किटी ने वर्ष 2022 में शहर के होटलों में अन्न की बर्बादी रोकने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बोर्ड उपलब्ध कराए थे। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम को दिए गए आवेदन की प्रति भी महापौर को सौंपी और निगम स्तर पर इस दिशा में प्रभावी प्रयास करने का अनुरोध किया। इस पर महापौर मंजुषा भगत ने आश्वासन दिया कि अन्न की बर्बादी रोकने के प्रयासों से जुड़े प्रस्ताव को एमआईसी की बैठक में रखा जाएगा। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि भोजन की बर्बादी रोकना भूख की समस्या कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हुनर को अजीबिका से जोड़ने पर जोर : महापौर ने कहा कि सेवा किटी महिलाओं को सीखने,अपनी प्रतिभा निखारने और अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाने का मंच दे रही है। ऐसी पहल समाज में

सकारात्मक बदलाव लाने के साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और युवतियों के बनाए उत्पादों को खरीदने तथा उनके लिए ऑर्डर देने की अपील की,ताकि उनके कौशल को रोजगार और आय का साधन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पादों को प्रोत्साहन देना केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है,बल्कि इससे उनके आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलती है। एमआईसी सदस्य श्वेता गुप्ता ने कहा कि अभिरुचि केंद्र के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को कई तरह की उपयोगी चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को अपनी क्षमताएं पहचानने,नए कौशल विकसित करने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

काउंसिलिंग से लेकर रंगोली और हस्तशिल्प तक का प्रशिक्षण : अभिरुचि केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए डॉ. तुषि

विश्वास,पारिवारिक परामर्श के लिए जानकी सिंह, करियर गाइडेंस के लिए अनामिका चक्रवर्ती वर्मा,सेल्फ मेकअप के लिए अनुभा डबराल,रंगोली के लिए चेतना मुंजे, नृत्य के लिए आभा वर्मा, हस्तशिल्प में प्रियंका चौबे और सरस्वती सोनी सहित सेवा किटी की अन्य सदस्यएं मौजूद रहीं। सोनी सिन्हा,मधु चौधरी,संजीता स्वर्णकार,सत्या दुबे, मिलन शर्मा,ज्योति द्विवेदी,सुधा तिवारी,दीपमाला सिंह,सुनीता दास,अंजना परिहार, च्यती अग्रवाल,श्रद्धा खेरपाण्डे,संजीता सोनी,स्मिता तिवारी,नमिता चावला और नेहा वर्मा सहित लगभग 15 प्रशिक्षार्थियों ने भी सहभागिता की।

22 अक्टूबर से पांच दिवसीय सेल्फ मेकअप कोर्स : सेवा किटी की ओर से आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 22 अक्टूबर से पांच दिवसीय सेल्फ मेकअप कोर्स शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे। अभिरुचि केंद्र के माध्यम से सेवा किटी का प्रयास महिलाओं और बालिकाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनके हुनर को आत्मनिर्भरता का आधार बनाना है।

15 दिन में सड़क-नाली का काम शुरू नहीं हुआ तो निगम का घेराव

नवगढ़ वार्ड के घुंटाघाट,हुसैनी नगर और महामयाघाट के खबारी बहल सड़क व बजबजाली नाली से घेराव



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नवागढ़ वार्ड क्रमांक 14 के घुंटाघारा, हुसैनी नगर और महामयाघारा में सड़क व नाली का निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। समस्या के निराकरण की मांग को लेकर 13 अक्टूबर को पार्थद मो. बाबर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और बहल सड़क व बजबजाली नालियों से हो रही परेशानी से अवगत कराया। वार्डवासियों ने बताया कि लंबे समय से सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। नालियों की बहल स्थिति से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। इस पर निगम आयुक्त ने शीघ्र निर्माण कराने का आश्वासन दिया। पार्थद मो. बाबर ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सड़क व नाली निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वार्डवासियों के साथ नगर निगम का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मो. खरीफ खान,युसुब अंसारी,खाजिद,बबल शर्मा,असरफ मुन्ना,वसीम मंसुरी सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे।

नो-एंट्री में घुसे 15 वाहन चालक,यातायात पुलिस ने 21 मामलों में वसूला 39,200 रुपए जुर्माना

रामानुजगंज में विशेष वाहन जांच अभियान,किचम तोड़ने वालों पर कार्रवाई...एसपी वैभव बैकर के निर्देश पर यातायात पुलिस की सक्ती

—संवाददाता—

बलरामपुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रामानुजगंज में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान नो-एंट्री नियम का उल्लंघन करने वाले 15 वाहन चालकों सहित कुल 21 मामलों में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने इन मामलों में कुल 39 हजार 200 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी विमलेश देवांगन के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों के बावजूद नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने वालों को पकड़ा गया। इसके अलावा यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की गई।

नो-एंट्री उल्लंघन पर विशेष नजर : शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए पुलिस ने प्रतिबंधित गांवों पर वाहनों की आवाजाही की जांच की। अभियान में नो-एंट्री के 15 मामलों के अलावा यातायात नियमों के



उल्लंघन के छह अन्य प्रकरण सामने आए। सभी 21 मामलों में मिलाकर 39,200 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

चालान से बचने नहीं, सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी : कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया। पुलिस ने कहा कि नो-एंट्री के प्रतिबंधों का पालन करना, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और यातायात संकेतों का सम्मान करना जरूरी है। नियमों की अनदेखी से न केवल चालक,बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने दोपहिया वाहन

चालकों से हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने तथा शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने की भी हिदायत दी गई।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने पर भी जोर दिया गया। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा में भी सहयोग करें।

बांकी बांध की नहर की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण,जेसीबी से कार्रवाई



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

बांकी बांध की मुख्य नहर की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मंगलवार सुबह प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया। एसडीएम बन सिंह नेताम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया। उक्त जमीन जल संसाधन विभाग की बताई जा रही है।दरअसल भाजपा नेता आलोक दुबे व कांग्रेस नेता परवेज आलम ने नहर की जमीन पर अतिक्रमण और उसके कथित अवैध क्रय-विक्रय की शिकायत कलेक्टर से

अलग-अलग की थी। शिकायत में श्रीगढ़ लुचकी ग्राम पंचायत के कांतीप्रकाशपुर क्षेत्र में दरिमा मोड़ से बाधुपारा तालाब तक करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में नहर की जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत कर्ता के अनुसार, जमीन पर डामर सड़क बनाकर लोह का बड़ा गेट भी लगा दिया गया है। शिकायत कर्ता ने बताया कि संबंधित भूमि जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन है। इस संबंध में पहले भी विभाग को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। मंगलवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।



स्वास्थ्य सेवाओं में सूरजपुर का दोहरा परचम ! आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रदेश में अव्वल, एनक्यूएस में महंगई को 91.05 प्रतिशत अंक

आयुष्मान कार्ड निर्माण में 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा, अब तक 7.67 लाख से अधिक कार्ड बने...

जिले के 76 स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत सफल

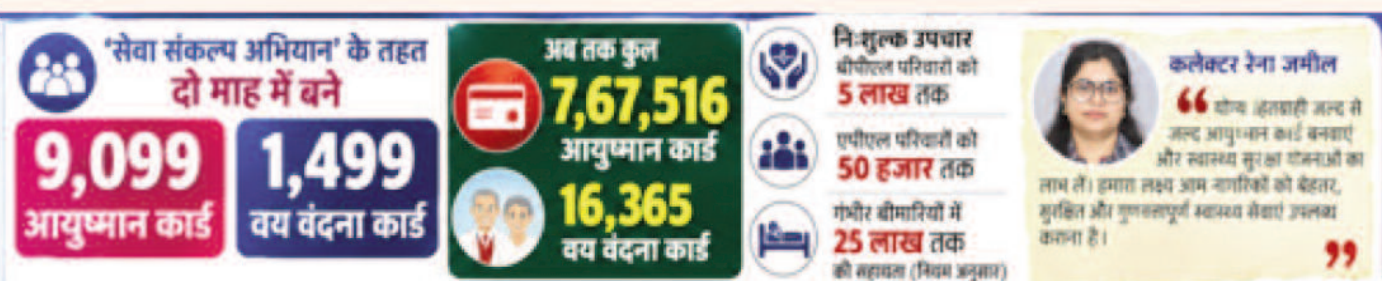
कलेक्टर रेना जमील और टीएएमएओ डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर उपचार की गुणवत्ता सुधारने तक प्रयास

'सेवा संकल्प अभियान' के तहत दो माह में बने 9,099 आयुष्मान कार्ड और 1,499 वय वंदना कार्ड

ऑनकार पाण्डेय

सूरजपुर, 13 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में सूरजपुर जिले से दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई हैं, एक ओर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण में सूरजपुर ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया है और निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 97 प्रतिशत कार्ड निर्माण पूरा किया है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएस) के मूल्यांकन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महंगई ने 91.05 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ने और स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने से जुड़ी ये उपलब्धियां जिले के स्वास्थ्य विभाग के लिए महत्वपूर्ण हैं, आयुष्मान कार्ड निर्माण से जरूरतमंद परिवारों को निर्धारित नियमों के तहत स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने का रास्ता मिलता है, वहीं NQAS मूल्यांकन स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, मरीजों की सुरक्षा और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता परखने का माध्यम है, कलेक्टर रेना जमील एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।



आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रदेश में पहला स्थान

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण में सूरजपुर जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 97 प्रतिशत कार्ड निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जिले में अब तक कुल 7.67.516 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, वहीं, राज्य शासन के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पिछले दो माह में 9,099 आयुष्मान कार्ड और 1,499 वय वंदना आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, यह अभियान उन पात्र परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, जो अब तक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायत विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से हितग्राहियों को पहचान और कार्ड निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं।

7.67 लाख से अधिक कार्ड, वरिष्ठ नागरिकों पर भी जोर...

जिले में अब तक 7.67.516 आयुष्मान कार्ड के साथ 16,365 वय वंदना आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जानकारी दी गई है, वय वंदना कार्ड निर्माण के माध्यम से 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, राज्य शासन द्वारा 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित लोगों तक पहुंचना और उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दिलाना है, हालांकि, 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने के बाद शेष पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना भी महत्वपूर्ण है, कार्ड निर्माण की उपलब्धि तभी अधिक उपयोगी साबित होगी, जब पात्र नागरिकों को योजना की जानकारी हो और जरूरत पड़ने पर वे संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

एनक्यूएस मूल्यांकन में महंगई स्वास्थ्य केंद्र को 91.05 प्रतिशत अंक

आयुष्मान कार्ड निर्माण की उपलब्धि के साथ जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सुधार से जुड़ी सफलता भी सामने आई है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएस) के मूल्यांकन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महंगई ने 91.05 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, यह मूल्यांकन स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं, स्वच्छता व्यवस्था, संक्रमण नियंत्रण, मरीजों की सुरक्षा, उपलब्ध संसाधनों और उपचार की

फॉरिस्ट कॉलोनी और जनपद चौक में विधि-विधान से हुई मां दुर्गा की स्थापना, प्रतिदिन भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे श्रद्धालु

शक्ति की भक्ति में डूबा सोनहत, मां दुर्गा के जयकारों से गूँजे पंडाल

—संवाददाता—
सोनहत (कोरिया), 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा सोनहत क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति और आराधना में सराबोर हो गया है। चारों ओर माता के जयकारों, भक्ति गीतों और धार्मिक आयोजनों से भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया है, नवरात्रि के आगमन के साथ ही क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना प्रारंभ की गई। विशेष रूप से फॉरिस्ट कॉलोनी और जनपद चौक के समीप स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण और आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं, दोनों स्थानों पर आकर्षक पंडालों का निर्माण कर विद्युत सज्जा की गई है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई स्थापना

नवरात्रि के प्रथम दिवस रविवार की संस्था को पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। पूजा-अर्चना के साथ घटस्थापना कर नौ दिनों तक चलने वाली देवी आराधना का शुभारंभ हुआ, श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की, प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना के साथ भक्तों ने नवरात्रि का शुभारंभ किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री का स्वरूप शक्ति, धैर्य, स्थिरता और दृढ़ आस्था का प्रतीक माना जाता है। माता के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने परिवार और क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई, सुबह से ही पूजा स्थलों और



आस्था, उत्साह और भक्ति से सराबोर सोनहत

शारदीय नवरात्रि ने सोनहत में धार्मिक उल्लास की नई छटा बिखेरी दी है, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं, सुसज्जित पंडालों, नियमित पूजा-अर्चना, महाआरती और प्रतिदिन आयोजित भंडारे के माध्यम से क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है, श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं, आने वाले दिनों में भी पूजा-पंडालों में धार्मिक गतिविधियों के जारी रहने से क्षेत्र में नवरात्रि की रौनक बनी रहने की उम्मीद है, मां दुर्गा के जयकारों से गुंजाता सोनहत इन दिनों शक्ति की उपासना, सेवा और सामाजिक सद्भाव का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, भक्तों ने माता को रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम और साधना की प्रतीक हैं, उनकी आराधना से भक्तों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और जीवन में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है, नवरात्रि के इन पावन दिनों में पूजा-पाठ और मंत्रोच्चार के बीच सोनहत का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आ रहा है।

रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाए पंडाल महाआरती में शामिल हो रहे भक्त

फॉरिस्ट कॉलोनी और जनपद चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, रंग-बिरंगी विद्युत झालरों और रोशनी से सजे पंडाल शाम होते ही श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं, महाआरती के दौरान

दीपों की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है, भक्ति गीतों की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालु माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना में शामिल हो रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में नवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु परिवार सहित पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

प्रतिदिन भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं को करिया जा रहा प्रसाद ग्रहण

नवरात्रि के दौरान पूजा-अर्चना के साथ सेवा और धार्मिक सद्भाव की भावना को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है, फॉरिस्ट कॉलोनी और जनपद चौक के दुर्गा पूजा स्थलों पर प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भक्तिभाव से प्रसाद

ग्रहण कर रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों को प्रसाद वितरित करने के साथ सामूहिक रूप से भोजन कराने की व्यवस्था की जा रही है, भंडारे में सहभागिता से धार्मिक आस्था के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश भी प्रसारित हो रहा है, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूजा समितियों और आयोजन से जुड़े लोगों की सक्रियता से धार्मिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है, प्रतिदिन आयोजित होने वाले भंडारा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।

व्यवस्था बनाए रखने में जुटे समिति के सदस्य

नवरात्रि के दौरान पंडालों में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आयोजन समितियों के सदस्य व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में जुटे हुए हैं, दर्शनार्थियों की सुविधा, पूजा कार्यक्रमों के संचालन और भंडारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, समितियों से जुड़े लोग धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, नवरात्रि के अवसर पर सोनहत में दिखाई दे रहा उत्साह धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकजुटता का भी परिचायक है।

भूमि पट्टा, मुआवजा, सड़क निर्माण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित विभिन्न मामलों को लेकर पहुंचे आवेदक

एमसीबी, 13 अक्टूबर

2026। जनदर्शन में पोटाडंड निवासी सोनिया गोंड एवं अर्जुन सिंह ने भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। पहाड़हसवाही निवासी फूलमती ने पुरतानी कब्जे की भूमि की जांच कर पात्रतानुसार पट्टा प्रदान कराने का अनुरोध किया। इसी प्रकार केराडोल निवासी राक़ी, राजेंद्र कुमार, मलराज एवं भईयालाल ने भूमि और पट्टे से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग की। पिपरिया निवासी तिलधारी एवं रामबाई ने भी भूमि संबंधी मामलों को लेकर अपनी समस्याएं रखीं।

देवगुड़ी निर्माण एवं अथरी सड़क का मामला उठा

चनवारीडांड के समस्त ग्रामवासियों ने देवगुड़ी निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने तथा शिकायत के आधार पर संबंधित सरपंच, सचिव एवं इंजीनियर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। वहीं साल्ही निवासी सरपंच केवल सिंह मरकाम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अथरी सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

मुआवजा, प्रमाण-पत्र और

लंबित शिकायतों के निराकरण की मांग

शंकरगढ़ निवासी रामचंद्र ने मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। खोंगापानी निवासी अर्चना सिंह ने टीसी एवं माइगेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। वहीं खोंगापानी निवासी राकेश कुमार बंसल ने पूर्व में प्रस्तुत शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं होने की बात रखते हुए उसके निराकरण की मांग की। जनदर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों तक पहुंचाना और उनके निराकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि पात्र आवेदकों को राहत मिल सके।



सुराजपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई सौगात

अटल आरोग्य लैब, सीटी स्कैन निरीक्षण, रक्तदान शिविर और चिकित्सा वाहन

36 प्रकार की निःशुल्क जांच से मरीजों को बड़ी राहत, अटल आरोग्य लैब का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ

सुराजपुर जिला चिकित्सालय में मई से संचालित लैब में अब तक 44,125 मरीजों की जांच, प्रतिदिन 600 से 700 मरीजों के नमूनों की जांच का दावा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वार्डों में मरीजों से लिया फीडबैक, डायलिसिस और सिटी स्कैन यूनिट का किया निरीक्षण, सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का बढ़ाया उत्साह...

—ओंकार पाण्डेय—

सुराजपुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण गतिविधि हुई, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सुराजपुर में अटल आरोग्य लैब का विधिवत शुभारंभ किया, इस दौरान उन्होंने लैब परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध जांच सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, इसके बाद अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने डायलिसिस यूनिट और सिटी स्कैन यूनिट का भी निरीक्षण किया, इसी क्रम में जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और स्वेच्छिक रक्तदान को मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। जिला चिकित्सालय में संचालित अटल आरोग्य लैब में 136 प्रकार की चिकित्सकीय जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, विभागीय जानकारी के अनुसार, मई 2026 से शुरू हुई इस लैब के माध्यम से अब तक 44,125 मरीजों की विभिन्न जांचें की जा चुकी हैं, प्रतिदिन लगभग 600 से 700 मरीजों के रक्त नमूनों की जांच होने की जानकारी दी गई है, यह सुविधा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी

क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए राहत का माध्यम बन रही है, जांच के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करने की जरूरत कम होने से मरीजों के समय और धन की बचत होने की उम्मीद है। 136 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क जिला चिकित्सालय सुराजपुर में स्थापित अटल आरोग्य लैब का संचालन मई 2026 से प्रारंभ किया गया था, अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसका विधिवत शुभारंभ किया, इस अवसर पर उन्होंने लैब परिसर में उपलब्ध सुविधाओं और जांच संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, अटल आरोग्य लैब में 136 प्रकार की विभिन्न चिकित्सकीय जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, किसी बीमारी की पहचान और उपचार की दिशा तय करने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे में सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच सुविधा मिलने से मरीजों को उपचार के दौरान होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है, कई बार मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद जांच कराने के लिए निजी प्रयोगशालाओं का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उपचार का खर्च बढ़ जाता है, जिला चिकित्सालय में उपलब्ध निःशुल्क जांच सुविधाएं इस आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं, हालांकि, जांच सुविधा का वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीजों को आवश्यक जांच समय पर उपलब्ध हो, रिपोर्ट निर्धारित समय में मिले और

जांच के परिणामों के आधार पर उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ सके, इसलिए लैब के नियमित संचालन और जांच की गुणवत्ता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

अब तक 44,125 मरीजों की जांच, प्रतिदिन 600 से 700 नमूनों की जांच स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अटल आरोग्य लैब के माध्यम से अब तक लगभग 44,125 मरीजों की विभिन्न चिकित्सकीय जांचें की जा चुकी हैं, लैब में प्रतिदिन लगभग 600 से 700 मरीजों के रक्त नमूनों की जांच किए जाने की जानकारी दी गई है, लैब में आधुनिक मशीनों एवं जांच उपकरणों की सहायता से कम समय में रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, इससे चिकित्सकों को मरीजों की बीमारी की पहचान करने और आवश्यक उपचार शुरू करने में सहायता मिलती है, जांच रिपोर्ट समय पर मिलने से मरीजों को उपचार संबंधी निर्णय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने में भी मदद मिल सकती है, जिला चिकित्सालय में एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की जांच उपलब्ध होना मरीजों के लिए सुविधाजनक है, खासकर उन मरीजों के लिए, जिन्हें बार-बार अलग-अलग केंद्रों पर जाकर जांच करानी पड़ती है। निःशुल्क जांच की सुविधा से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, इस उपलब्ध के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लैब में जांच के लिए आवश्यक उपकरण, तकनीकी संसाधन

और संबंधित कर्मचारी नियमित रूप से उपलब्ध रहें, ताकि बढ़ती संख्या में आने वाले मरीजों को सुविधा मिलती रहे।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित
कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन श्री बाबूलाल अग्रवाल, वाइस चेयरमैन ओंकार पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, जनपद पंचायत सुराजपुर की अध्यक्ष स्वाति सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह, सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सुविधाओं का लाभ मरीजों तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण
सुराजपुर जिला चिकित्सालय में अटल आरोग्य लैब के माध्यम से 136 प्रकार की निःशुल्क जांच उपलब्ध कराना और अब तक 44,125 मरीजों की जांच किए जाने की जानकारी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को दर्शाती है, प्रतिदिन बड़ी संख्या में नमूनों की जांच होने से लैब की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, अब जरूरी है कि मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ लगातार मिलता रहे, जांच की गुणवत्ता, रिपोर्ट की समयबद्ध उपलब्धता, डायलिसिस

वार्डों में मरीजों से मिले स्वास्थ्य मंत्री, व्यवस्थाओं पर लिया फीडबैक

अटल आरोग्य लैब के शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उपचार के दौरान मिल रही सेवाओं के बारे में फीडबैक प्राप्त किया, अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद करने से उन्हें उपचार के दौरान आने वाली कठिनाइयों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है, मरीजों का अनुभव स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, स्वास्थ्य मंत्री ने डायलिसिस यूनिट और सिटी स्कैन यूनिट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इन इकाइयों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा और मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, डायलिसिस और सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन सेवाओं की उपलब्धता से मरीजों को जांच और उपचार के लिए अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत कम हो सकती है, हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का नियमित संचालन, तकनीकी व्यवस्था और मरीजों को समय पर सेवा उपलब्ध कराना आवश्यक है, मरीजों से लिया गया फीडबैक तभी सार्थक होगा, जब उससे सामने आने वाली समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई हो और अस्पताल की व्यवस्था में लगातार सुधार किया जाए।

रक्तदान शिविर में पहुंचे मंत्री, रक्तदाताओं का बढ़ाया उत्साह

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सुराजपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिविर का अवलोकन कर स्वेच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्त की एक यूनिट जरूरतमंद मरीज का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, दुर्घटना, गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर रक्त की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है, ऐसे में स्वेच्छिक रक्तदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य से जोड़ना जरूरी है, उन्होंने स्वस्थ एवं पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से नियमित रक्तदान के लिए आगे आने और मानव सेवा के इस कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की, रक्तदान शिविर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके साथ नियमित जागरूकता, स्वेच्छिक रक्तदाताओं की भागीदारी और आवश्यकता के समय रक्त की उपलब्धता बनाए रखना भी आवश्यक है।

एवं सिटी स्कैन जैसी सुविधाओं का सुचारु संचालन और मरीजों की समस्याओं का समय पर समाधान स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए, अटल आरोग्य लैब, मरीजों से संवाद और रक्तदान शिविर—तीनों पहलें जनस्वास्थ्य से जुड़ी हैं, इनका वास्तविक महत्व तभी बढ़ेगा, जब जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाएं जरूरतमंद मरीजों को नियमित रूप से, समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलती रहेंगी।

महिला मानस प्रतियोगिता में आंजोरपुर की प्रज्ञा मानस मंडली प्रथम

—संवाददाता—

अंबिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

विजयादशमी महोत्सव 2026 के तहत कलाकेंद्र मैदान में मंगलवार को संभाग स्तरीय महिला रामचरितमानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरगुजा सेवा समिति, नागरिक समिति एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिला मानस मंडलियों ने रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों का भावपूर्ण गायन कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। प्रतियोगिता में प्रज्ञा मानस मंडली आंजोरपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में मां शारदा मानस मंडली बतारा दूसरे और कौशलेन्द्र मानस मंडली रामानुजनगर तीसरे स्थान पर रही। मुख्य निष्पत्ति श्रीमती पूर्णिमा पटेल एवं दिनेश कुमार मिश्र के मूल्यांकन के आधार पर प्रज्ञा मानस मंडली आंजोरपुर को 100 में से 79 अंक, मां शारदा मानस मंडली बतारा को 76 अंक तथा कौशलेन्द्र मानस मंडली रामानुजनगर को 75 अंक मिले। इसके अलावा मां संतोषी दुर्गा मानस मंडली पिपरा, ज्योति मानस मंडली खरवत, मां शारदा मानस मंडली उदयपुर, मां कामेश्वरी मानस मंडली गिरजाही और शिव मानस मंडली लटमा ने भी अपनी प्रस्तुतियों से

मां शारदा मानस मंडली बतारा को दूसरा और कौशलेन्द्र मानस मंडली रामानुजनगर को मिला तीसरा स्थान, आज पुरुष मानस मंडलियों की प्रतियोगिता और राम रूप सज्जा का आयोजन



श्रोताओं की सराहना प्राप्त की। खेलक, मंजीरे और हारमोनियम की संगत पर प्रस्तुत मानस गायन ने पूरे आयोजन स्थल को भक्तिमय बना दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्रीराम दरबार, मां दुर्गा की भी स्वरूपों और मां सरस्वती की पूजा-अर्चना एवं आरती के साथ हुआ। इस दौरान रामचरितमानस गायन प्रतियोगिता को व्यापक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय

पंडित रविशंकर त्रिपाठी का स्मरण किया गया। अतिथियों और समिति पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

आयोजन में नगर निगम अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, एमआईसी सदस्य, पार्षद तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सरगुजा सेवा समिति की

अध्यक्ष श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, नागरिक समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, अनिल सिंह (मेजर), भारत सिंह सिसोदिया, महासचिव मधुसूदन शुक्ला, ललन प्रताप सिंह, आलोक दुबे, दीपक सोनी, राजेश कश्यप, पीयूष कुमार त्रिपाठी सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, महिलाओं और रामभक्तों ने मानस गायन का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सिंह टुटेजा और वीर सोनी ने संयुक्त रूप से किया।

आज पुरुष मानस मंडलियों की प्रतियोगिता
विजयादशमी महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार, 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कलाकेंद्र मैदान में संभाग स्तरीय पुरुष मानस मंडलियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए राम रूप सज्जा प्रतियोगिता भी होगी। सरगुजा सेवा समिति ने धर्मप्रेमी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजन में सहभागिता करने की अपील की है। उक्त जानकारी समिति के प्रचार-प्रसार प्रमुख एवं मीडिया प्रभारी पीयूष त्रिपाठी ने दी।

ग्लैमर के साथ समाजसेवा की झलक, अंबिकापुर में उर्वशी रौतेला व अक्षरा सिंह का दिखेगा जलवा

15 को बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, 16 को भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह करेंगी शिरकत, सरगवां पैलेस रिसॉर्ट में सजेगी डाइया की मत्वा शाम

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 13 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

नवरात्रि की भक्ति, गरबा की थाप, डाइया की खनक और फिल्मी सितारों की मौजूदगी इन सबका संगम देखने को मिलेगा अंबिकापुर में आयोजित होने जा रहे भव्य आयोजन 'डाइया रास अंबिकापुर' में। 15 और 16 अक्टूबर को सरगवां द पैलेस रिसॉर्ट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मॉडल उर्वशी रौतेला और भोजपुरी अभिनेत्री एवं लोकप्रिय गायिका अक्षरा सिंह विशेष आकर्षण रहेंगी।



रौतेला की दुनिया से समाज सेवा तक उर्वशी रौतेला

बॉलीवुड की चकाचौंध और अपनी खूबसूरती के लिए चर्चित उर्वशी रौतेला का व्यक्तित्व मनोरंजन जगत तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक कार्यों और धार्मिक आयोजनों में उनकी भागीदारी भी समय-समय पर चर्चा में रही है। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनके आर्थिक योगदान की खबरें सामने आई थीं। वहीं, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने में उनके योगदान की भी रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के

बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव के दौरान उनकी भागीदारी और अनूपूर्णा रसोई में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने की तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ऐसी गतिविधियां लोकप्रिय हस्तियों के दूसरे पहलू को सामने लाती हैं। अब उर्वशी रौतेला 15 अक्टूबर को अंबिकापुर में आयोजित डाइया रास में शिरकत करेंगी। नवरात्रि के उल्लास के बीच उनकी मौजूदगी आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी। 16 अक्टूबर को अक्षरा सिंह की आवाज का जादू डाइया रास की दूसरी शाम भोजपुरी सुरीला और संगीत जगत की लोकप्रिय कलाकार अक्षरा सिंह के नाम रहेगी। अपनी दमदार आवाज, अभिनय और आकर्षक मंचीय अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अक्षरा सिंह ने भोजपुरी संगीत के साथ-साथ भक्ति गीतों में भी अपनी पहचान बनाई है।

